

राह में पग-पग पर बाधाएं



गतिरोध
मांग 110 लाख
यूनिट प्रतिदिन,
आपूर्ति हो रही मात्र
80 लाख

उपलब्ध बिजली का
भी ठीक तरीके से
नहीं हो रहा वितरण



हो रहे हैं उपाय : बिजली मंत्री

प्रदेश के बिजली मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार सरकार हर वर्ग को पूरी बिजली देने के लिए कृत संकल्प है और जो भी गतिरोध हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है। बिजली की कमी न रहे, इसके लिए बाहरी राज्यों से बिजली खरीदने की योजना पर काम हो रहा है। ओवरलोड सिस्टम की समस्या को देखते हुए पिछले दिनों 66करों के कई सबस्टेशनों पर अधिक क्षमता वाले ड्रांसफार्मर लगाए गए हैं।

साथ ही जर्जर लाइनों को बदला जा रहा है। कर्मियों की कमी है, लेकिन जब तक नई भर्ती नहीं हो जाती, तब तक आउटसोर्सिंग से काम लिया जा रहा है।



महेंद्र प्रताप सिंह



सुनील गुलाटी



एस गुलाटी

व्यवस्था ढर्वे पर नहीं आई

एफआई के पूर्व प्रधान उदयमी सुनील गुलाटी के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से काम न होने व काम में इमानदारी का अभाव ऐसे प्रमुख कारक हैं, जिस वजह से आज तक बिजली व्यवस्था ढर्वे पर नहीं आई। कानेफेडरेशन ऑफ आरडल्यूए के महासचिव एस गुलाटी कहते हैं कि बढ़ती शहरी आवादी व विकास के अनुरूप सरकार ने जलरी कदम नहीं उठाए। दूसरा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की ज्यादा कोशिशें होनी चाहिए। व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भाटिया के अनुसार बिजली न होने से व्यापार-उद्योग धंधे चौपट हैं और पिछले छह वर्षों से यह सुनते सुनते लोगों के कान पक गए हैं कि अगले दो साल में 24 घंटे बिजली मिलेगी। ड्रांसफोर्ट सुरेश अरोड़ा कहते हैं कि ग्रेटर फरीदाबाद के रूप में एक और बाया शहर विकसित हो रहा है। आईएमटी बनने की बात हो रही है। इसके लिए बिजली कहां से आएगी, इस बारे में जंभीरता से सोचने की जरूरत है।



जगदीश भाटिया



सुरेश अरोड़ा

बिजली की कमी

पूरे प्रदेश में इस समय 11 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत है। इसके मुकाबले उपलब्धता सिर्फ चार हजार मेगावाट के आसपास है।

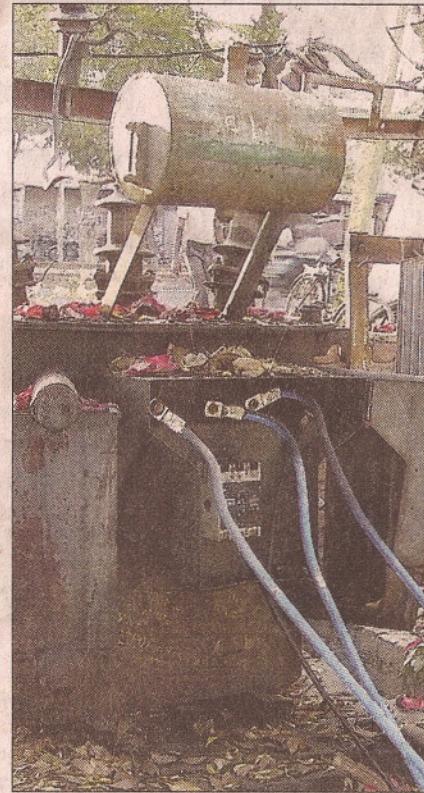
सिस्टम पर ओवरलोड

बिजली निगम के विभिन्न 33 व 66करों की सबस्टेशन ओवरलोड हैं। इस कारण जो बिजली उपलब्ध भी होती है तो उसका भी समुचित ढंग से वितरण नहीं हो पाता, क्योंकि सिस्टम गर्म हो जाता है और उसे नियमित अंतराल पर बंद न किया जाए तो उसके पूरी तरह से ठप होने का खतरा रहता है। यही वजह है कि थोड़े-थोड़े अंतराल पर बिजली दी जाती है।

एजेंसियों में नहीं तालमेल

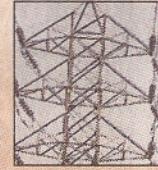
हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को तोड़ कर बिजली निगम बनाया गया, जिसमें वितरण के लिए डीएचबीवीएन, प्रसारण के लिए एचबीपीएन और उत्पादन के लिए एचपीजीसीएल को जिम्मेदारी दी गई।

इन तीनों एजेंसियों में कोई तालमेल नहीं है, जिसका स्मीथा असर अंत में समुचित बिजली आपूर्ति पर पड़ता है।



संसाधनों का अभाव

फ्यूज उड़ने, जंपर व लाइन टूटने की शिकायतें पिछली जर्मियों में कई बार सामने आई थीं।



चौंकि निगम में समुचित संसाधनों (सीढ़ी और हाइड्रोलिक वाहन) का अभाव है, ऐसे में लाइनमैन स्टाफ को मिनटों में दूर होने वाले फाल्ट को ढूँढ़ने में ही धंधे लगते हैं। इसके अलावा इस सिस्टम में आई खारबी को दूर करने के लिए तकनीकी कमी यानी सहायक लाइनमैन की जबर्दस्त कमी है।